SB NEWS

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

आपका भरोसा, हमारी ताकत

RNI No. : DELHIN/2016/70240

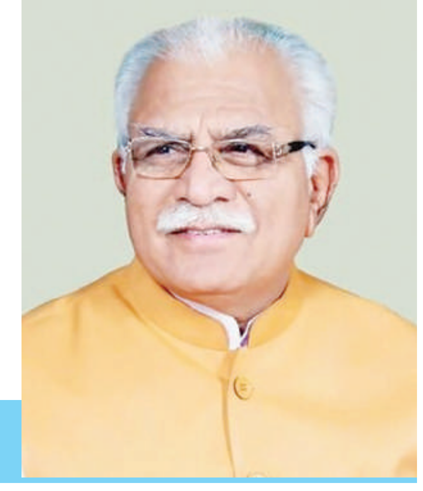

2 भारतीय मिसाइलों व रक्षा उपकरणों का बज... | 3 महिलाओं की समस्याओं एवं आकांक्षाओं को मोबाइल... | 4 हरियाणा सरकार के आशीर्वाद से सरकारी...

वर्ष: 9 | अंक: 179 | दिल्ली, गुरुवार, 24 अप्रैल 2025 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री सुक्खू ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की

हिमाचल प्रदेश (एजेन्सी)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की बुधवार को निंदा की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यहां जारी एक बयान में इसे कायरतापूर्ण हरकत करार देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं स्वीकार्य नहीं हैं और असामाजिक तत्वों पर हर कीमत पर नकेल कसी जानी चाहिए। सुक्खू ने बयान में कहा, इस बेहद दर्दनाक समय में हम मारे गए लोगों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम पीड़ितों के परिवारों और इस बर्बर कृत्य के प्रभावितों के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिवारों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। (मैं) घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पहलगाम में आतंकवादियों के हमले में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई तथा कई अन्य घायल हो गये। जान गंवानों वालों में अधिकतर पर्यटक थे।

पहलगाम आतंकी हमला बहुत दर्दनाक और अकल्पनीय : तेजस्वी यादव

पटना (एजेन्सी)। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को बहुत दर्दनाक बताते हुए कहा कि इस तरह पर्यटकों की जान लेना अकल्पनीय है। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने यहां पत्रकारों से यह भी कहा कि आतंकवादियों ने उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र पर हमला किया और गोलीबारी 20 मिनट तक जारी रही। नेता प्रतिपक्ष यादव ने कहा, हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते। यह बहुत दुखद घटना है। इस तरह से पर्यटकों की हत्या अकल्पनीय है। उन्होंने कहा, मृतकों में से एक बिहार का रहने वाला था, लेकिन वह हैदराबाद में तैनात था। हम सभी शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने गुप्तचर ब्यूरो के अधिकारी मनीष रंजन का जिक्र किया, जिनके पिता बहुत पहले पश्चिम बंगाल चले गए थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक की अध्यक्षता की

(एजेन्सी)।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और अन्य अधिकारी मौजूद हैं। अमित शाह जब अपने घर से 7-लोक कल्याण मार्ग के लिए निकल रहे थे, तो उस दौरान उनके हाथ में लाल रंग की फाइल थी। इस हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। सीतारमण अपनी आधिकारिक यात्रा को बीच में ही छोड़कर अमेरिका से वापस आ रही हैं।

प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को सऊदी अरब से सुबह-सुबह वापस आ गए। प्रधानमंत्री ने अपने आगमन के तुरंत बाद हवाई अड्डे पर एक बैठक की, जिसमें उन्होंने जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल के साथ जम्मू-कश्मीर आतंकी हमले पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री भी बैठक में मौजूद थे। इससे पहले, अमित शाह ने पहलगाम के बैसरन का दौरा किया, जहां आतंकवादियों ने हमला किया था। साथ ही उन्होंने उस अस्पताल का भी दौरा किया जहां कुछ घायलों को भर्ती कराया गया। पहलगाम हमले के एक दिन बाद जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने सुरक्षा समीक्षा बैठक की है। सूत्रों ने बताया कि पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादियों के हमले में 26 लोगों के मारे जाने के एक दिन बाद जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा समीक्षा बैठक की।

बैठक के दौरान, उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लोगों की हत्या का बदला लेने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह भी सुनिश्चित करेगी कि आतंकवाद के ऐसे कायराना कृत्य फिर न हों। बैठक में उपराज्यपाल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया है कि पहलगाम आतंकी हमले के अपराधियों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई के लिए सभी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और आतंकवाद के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से खत्म करना होगा। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घातक पहलगाम आतंकी हमले के बाद कल सर्वदलीय बैठक बुलाने का आह्वान किया है। पत्र में लिखा है कि मैं स्थिति पर चर्चा करने, आतंकी हमले की संयुक्त निंदा करने और शांति, न्याय और लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए आगे के रास्ते पर विचार-विमर्श करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुला रहा हूं।

'अटारी चेक पोस्ट की जाएगी बंद, पाकिस्तान के साथ सिंधू जल समझौता रोका जाएगा'

नई दिल्ली (एजेन्सी)। पहलगाम आतंकवादी हमले के एक दिन बाद विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। पहलगाम में हुए हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की मौत हो गई। कई अन्य घायल हो गए। विदेश सचिव ने कहा कि सीसीएस ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की कई सरकारों से समर्थन और एकजुटता की मजबूत अभिव्यक्ति मिली है, जिन्होंने इस आतंकी हमले की स्पष्ट रूप से निंदा की है। उन्होंने यह भी कहा कि सीसीएस ने ऐसी भावनाओं के लिए अपनी सराहना दर्ज की है, जो आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता को दर्शाती है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अटारी चेक पोस्ट की जाएगी बंद, पाकिस्तान के साथ सिंधू जल समझौता भी रोका जाएगा।

विजेंद्र गुप्ता और ओम बिड़ला ने दिल्ली विस को राष्ट्रीय धरोहर में बदलने पर की चर्चा

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने दिल्ली विधानसभा के पुस्तकालय को डिजिटल बनाने और ई-लाइब्रेरी के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने संसद सचिवालय में लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला से मुलाकात की। विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष की यह मुलाकात दिल्ली की विधायी विरासत के संरक्षण और आधुनिकीकरण पर संसद और विधानसभा के बीच सहयोग को लेकर हुई। यह बैठक दिल्ली विधान सभा के संस्थागत ढांचे को मजबूत करने, इसके बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और इसके कार्यों में डिजिटलाइजेशन तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के प्रयासों पर केंद्रित थी।

40 मिनट की विस्तृत बैठक के दौरान श्री गुप्ता ने लोकसभा अध्यक्ष को दिल्ली विधान सभा में चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी जिसमें विधानसभा के ऐतिहासिक परिसर को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में स्थापित करने के प्रयासों पर विशेष बल दिया। दिल्ली विधानसभा को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में विकसित करने की पहल दिल्ली की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का उत्सव मनाने के साथ-साथ इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुलभ और प्रासंगिक बनाए रखने का लक्ष्य रखती है।

लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला ने दिल्ली विधान सभा की पुस्तकालय को पूर्णतः डिजिटल बनाने और ई-लाइब्रेरी में परिवर्तित करने की योजना को तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। इस परिवर्तन से विधायी दस्तावेजों तक जनता की पहुंच सुलभ होगी और संस्थागत ज्ञान के संरक्षण को सुनिश्चित किया जाएगा।

श्री ओम बिड़ला ने दिल्ली विधानसभा के इन प्रयासों की सराहना की। श्री ओम बिड़ला ने संसद सचिवालय को दिल्ली विधान सभा के प्रयासों में हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्री गुप्ता ने यह भी बताया कि दिल्ली विधानसभा सचिवालय के सभी अभिलेख और कार्यवाही, इसकी स्थापना से लेकर अब तक, दिल्ली नगर निगम के ऐतिहासिक टाउन हॉल में व्यवस्थित रूप से संरक्षित हैं। इस अभिलेखीय कार्य के महत्व को समझते हुए, श्री बिड़ला ने इन अभिलेखों को डिजिटलीकरण परियोजना में शामिल करने के निर्देश दिए, जो भारत के विधायी इतिहास की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है।

यह उच्च स्तरीय बैठक भारत में केंद्रीय और राज्य विधायी निकायों के बीच एक महत्वपूर्ण सहयोग को दर्शाती है, जो विरासत संरक्षण को तकनीकी विकास के साथ जोड़ने का काम करती है।

सस्ते लोन्स से दिल्लीवासियों के घरों का सपना करें पूरा: रविन्द्र इन्द्राज

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। समाज कल्याण, एससी/एसटी कल्याण, चुनाव और सहकारिता मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड के अधिकारियों के साथ निगम के कार्यों और आगामी योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। सहकारिता मंत्री ने बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश दिए की सभी योजनाएँ दिल्ली वासियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाएं और सस्ते लोन के जरिए दिल्ली वासियों के अपने घर के सपने को पूरा करने की राह आसान करें।

सहकारिता मंत्री ने निर्देश दिए की विभाग को तकनीकी रूप से अपग्रेड करें ताकि लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आसान हो। झुग्गियों या कच्चे मकानों में रहने वालों को सस्ते लोन देने की प्रक्रिया भी आसान बनाएं। साथ ही पर्यावरण के अनुकूल कार्यों जैसे सोलर पावर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज में आधारभूत संरचना के कार्यों को वित्तीय प्रोत्साहन दें। इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड, एमएनआरई, डीयूएसआईबी और डीडीए विभागों से समन्वय बनाकर कार्य करें। श्री रविन्द्र इन्द्राज ने कहा की दिल्ली वासियों के लिए आवेदन प्रक्रिया से लेकर कार्य पूर्ण होने तक निर्धारित शुल्क के अलावा कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ ना लगे यह दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम सुनिश्चित करे।

सहकारिता मंत्री ने कहा की आरसीएस की निगरानी में डिफाल्टर्स से रिकवरी की प्रक्रिया भी तेज हो।

■ सहकारिता मंत्री ने दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड के साथ की समीक्षा बैठक

शहीद सिद्धार्थ का बलिदान युवाओं को देश सेवा के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा : मुख्यमंत्री

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी सेक्टर-18 स्थित फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव के निवास पहुंचकर उनके बलिदान पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की और शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाते हुए हरियाणा सरकार की ओर से हर संभव सहयोग दिए जाने का आश्वाशन दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत मां के महान सपूत के बलिदान पर पूरे देश को गर्व है। उन्होंने कहा कि देश पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ऐसे वीर सपूत को वे नमन करते हैं। शहीद सिद्धार्थ का बलिदान सदैव युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ ने छोटी सी आयु में आकाश में नई ऊंचाइयों को छुआ और जाते-जाते भी सिद्धार्थ ने सैकड़ों जिंदगियों को बचाने का कार्य किया।

गौरतलब है कि विगत 2 अप्रैल को फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव का जगुआर विमान गुजरात के जामनगर में प्रैक्टिस मिशन के दौरान उड़ान भरने के बाद सिटी के करीब 12 किलोमीटर दूर सुवरदा गांव के मैदान में क्रैश हो गया था। इस अवसर पर रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, सहित जिला प्रशासन अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे।

मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश

राजधानी में मौजूद सभी 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का थर्ड पार्टी कराया जाए ऑडिट

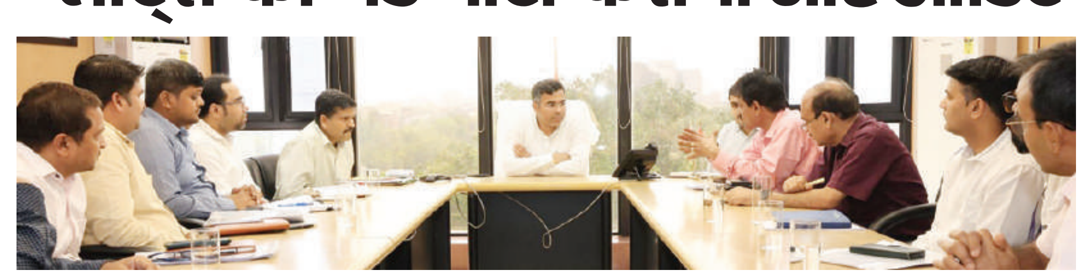

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। यमुना नदी की सफाई को लेकर गंभीर रुख अपनाते हुए दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश दिया है कि राजधानी में मौजूद सभी 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए।

डीजेबी के सीवेज प्रबंधन विभाग के साथ हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में मंत्री को वर्तमान ट्रीटमेंट क्षमता और अपग्रेडेशन व मरम्मत कार्यों की स्थिति की जानकारी दी गई। जल मंत्री ने कहा कि हमने डीजेबी को सभी एसटीपी का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वास्तव में कितनी ट्रीटमेंट क्षमता है और कितना ट्रीटमेंट किया जा रहा है। वर्तमान में 37 एसटीपी में से 18 का अपग्रेडेशन कार्य चल रहा है, जबकि सोनिया विहार, दिल्ली गेट और ओखला में तीन नए प्लांट्स बनने से लगभग 47 मिलियन गैलन प्रति दिन अतिरिक्त ट्रीटमेंट क्षमता बढ़ेगी।

जल मंत्री ने कहा कि फिलहाल बड़ी मात्रा में बिना ट्रीट किया गया सीवेज यमुना में जा रहा है। दिल्ली सरकार इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठा रही है। ऑडिट उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। रिपोर्ट के आधार पर भविष्य की कार्ययोजना तय की जाएगी।

यमुना में गिरने वाले सीवेज के ट्रीटमेंट को लेकर दिल्ली सरकार ने 2025-26 बजट में 500 करोड़ रुपये एसटीपी की मरम्मत के लिए और 250 करोड़ रुपये पुरानी सीवर लाइनों के प्रतिस्थापन के लिए आवंटित किए हैं। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, 37 में से 30 एसटीपी का संचालन निजी कंपनियों को सौंपा गया है। जल मंत्री ने इन ऑपरेटर्स को निर्देश दिया है कि वे एसटीपी की तय मानकों के अनुसार कार्यक्षमता सुनिश्चित करें। इससे पहले इसी महीने, श्री वर्मा ने घोषणा की थी कि एशिया का सबसे बड़ा वेस्टवॉटर ट्रीटमेंट प्लांट-ओखला में 564 एमएलडी की क्षमता वाला–पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। साथ ही, दिल्ली जल बोर्ड विकेन्द्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर भी काम शुरू कर चुका है।

यह ऑडिट और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की कवायद दिल्ली सरकार की उस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत यमुना को स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त बनाया जाना है।

यदि कोई आपसे रिश्वत मांगता है तो बताएं: भगवंत मान

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। उच्च गुणवत्ता वाली लिंक सड़कों के निर्माण परियोजना को लागू करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए लिंक सड़कों की परियोजना का शुभारंभ किया।

यहां स्थानीय टैगोर थिएटर में 'सड़क ढांचा विकास मिलनी' के दौरान संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 64,878 किलोमीटर लिंक सड़कें हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा 18,944 किलोमीटर लिंक सड़कों के नवीनीकरण और उन्नयन की परियोजना शुरू की जा रही है, जिस पर 3,459.95 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस मिलनी का मुख्य उद्देश्य लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करना है, क्योंकि ये लिंक सड़कें लोगों की जीवन रेखा मानी जाती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लिंक सड़कें प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, क्योंकि ये सड़कें जहां ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की मदद करती हैं, वहीं व्यापार और कारोबार को बढ़ावा देती हैं। भगवंत सिंह मान ने बताया कि इनमें से कई सड़कें ऐसी हैं, जो छह साल का निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद नहीं बन पाई थी। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण करने वाली कंपनी या ठेकेदार अगले पांच साल तक इन सड़कों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे।

पिछले समय में सड़क निर्माण में फैले भ्रष्टाचार पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रथा पूरी तरह अनुचित थी। उन्होंने कहा कि पहले सड़क निर्माण के टेंडर में ऊपर से लेकर नीचे तक 'हिस्सेदारी' होती थी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऐसी खराब स्थिति में ठेकेदारों को मजबूरन सड़कों की गुणवत्ता से समझौता करना पड़ता था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यह भ्रष्ट प्रथा खत्म हो गई है, इसलिए ठेकेदारों को निमार्णाधीन सड़कों की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान देना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा, "मुझसे पहले सत्ताधारियों ने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे केवल अपने रिश्तेदारों की बात सुनते थे।" मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें जमीनी स्तर का पूरा ज्ञान है। उन्होंने घोषणा की कि मंडी बोर्ड, लोक निर्माण विभाग और ठेकेदारों के बीच एक समन्वय कमेटी बनाई जाएगी, ताकि सड़क निर्माण में सभी मुद्दों का समाधान किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अधिकारी भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ठेकेदारों से सेवा भावना के साथ सड़कें बनाने का आग्रह किया, क्योंकि ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन रेखा हैं। भगवंत सिंह मान ने पंचायतों से अपील की कि वे इन सड़कों का निर्माण निर्धारित मापदंडों के अनुसार करने के लिए सड़कों की निर्धारित चौड़ाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार उनकी सरकार ने राज्य सरकार के कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू किया है। उन्होंने कहा कि लिंक सड़कों के सर्वे में इसकी मदद से सरकार ने 226.89 करोड़ रुपए की बचत की, क्योंकि 540 किलोमीटर ऐसी सड़कें सामने आईं जो केवल कागजों पर थी, जबकि जमीनी स्तर पर नहीं थी। उन्होंने कहा कि सड़कें बनाने से पहले सीवरेज सिस्टम और तार बिछाने का काम पूरा कर लिया जाना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि सड़क निर्माण की सही गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करने के लिए तीसरे पक्ष से वित्तीय ऑडिट करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने खनन के लिए उपयोग होने वाली 78 लिंक सड़कों की चौड़ाई को 10 फीट से बढ़ाकर 18 फीट करने का फैसला लिया है, और इन 389.17 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण पर 266.27 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि प्रदेश के मंडी ढांचे को देश भर में सबसे बेहतर माना जाता है। भगवंत सिंह मान ने दुख के साथ कहा कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास फंड के तहत 6,857 करोड़ रुपए के फंड रोक दिए हैं, क्योंकि पिछली सरकार ने इस योजना के तहत फंड का कहीं और उपयोग कर लिया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की पैरवी भारत सरकार के समक्ष जोरदार तरीके से की जा रही है, जिसने मंडी विकास शुल्क को भी 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया है। नहरी पानी के महत्व का उल्लेख करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि जब उन्होंने पदभार संभाला था, तब प्रदेश में सिंचाई के उद्देश्यों के लिए केवल 21 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग हो रहा था। उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि आज 75 प्रतिशत नहरी पानी सिंचाई के लिए उपयोग हो रहा है, और इसे 80 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पदभार संभालने के बाद प्रदेश में 15,947 नहरों को पुनर्जनन किया है, जिसके कारण दूर-दराज के गांवों में भी पानी टेल तक पहुंच गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को पुनर्जनन करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले अपने बच्चे को सरकारी स्कूल भेजना आम आदमी की मजबूरी थी, लेकिन अब शिक्षा प्रणाली को नया रूप दिया जा रहा है, इसलिए अब बच्चे को सरकारी या निजी स्कूल में पढ़ाना माता-पिता की मर्जी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने देश में अपनी तरह की अनूठी पहल की है, जिसके तहत प्रदेश और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और कीमती जिंदगियां बचाने के लिए समर्पित रूप से 'सड़क सुरक्षा फोर्स' का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से प्रशिक्षित, नव भर्ती किए गए 1,597 कर्मचारी, जिनमें लड़कियां भी शामिल हैं, इस बल की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्हें पूरी तरह से सुसज्जित 144 वाहन प्रदान किए गए हैं।

जेल में बंद अपराधी कोई गुलाम नहीं : दिल्ली उच्च न्यायालय

नई दिल्ली (एजेन्सी)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बलात्कार और हत्या से जुड़े एक मामले में सजायाफ्ता एक व्यक्ति की पैरोल अर्जी यह कहते हुए स्वीकार कर ली कि सिर्फ इसलिए कि कोई अपराधी 20 साल से अधिक समय से जेल में है, उसके साथ गुलाम जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता ने अपने अपराध के लिए दो दशक से अधिक समय जेल में बिताया है। न्यायमूर्ति कृष्णा ने 16 अप्रैल के अपने फैसले में कहा, उसे जीवन के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सिर्फ इसलिए कि वह जेल में कैद है, उसके साथ गुलाम जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता, जिसे कोई बुनियादी मौलिक मानवाधिकार हासिल नहीं है। अब समय आ गया है कि जेल अधिकारी ऐसे मामलों से निपटने में थोड़ी अधिक संवेदनशीलता दिखाएं। बलात्कार और हत्या के मामले में सजायाफ्ता व्यक्ति ने पैरोल पर चार हफ्ते के लिए रिहा किए जाने के अनुरोध को लेकर उच्च न्यायालय का रुख किया था।

JAIS UNIFORMS
JAISWAL WARDI WALE
Manufacturer and Traders of School and Corporate Uniforms

Shop : B-18/G3, B-Block (Near Gate No. 5), Main Market, Dilshad Garden, Delhi - 110095
Factory : A-41, Industrial Area, Dilshad Garden, Delhi - 110095
(M) : 9990871005 • 8383956200

सम्पादकीय

चुनाव आयोग पर राहुल का निशाना

राहुल गांधी इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं ही, उन्हें एक बड़े नेता के तौर पर भी देखा जाता है। देश में तो राहुल गांधी भाजपा एवं उसकी एनडीए सरकार के खिलाफ संसद के भीतर-बाहर अभियान छेड़े हुए हैं ही, विदेशों में वह प्रवासी भारतीयों, छात्रों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों से वे लोकतंत्र के लिए अपनी चिंताओं को साझा करते हैं। राहुल अभी अमेरिका प्रवास पर हैं। वहां उन्होंने अपनी पहली सभा में भारत के केंद्रीय निर्वाचन आयोग की कार्यपद्धति की जमकर आलोचना की। किस तरह से पूरी निर्वाचन पद्धति सत्तारूढ़ भाजपा के पक्ष में काम करती है, उन्होंने इसका लेखा-जोखा सामने रखा है। अमेरिका के बोस्टन शहर पहुंचे राहुल ने व्यवसायियों और वहां रहने वाले भारतीयों से बातचीत में भारत के चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 'हमारे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और निर्वाचन प्रणाली में व्यापक गड़बड़ियां हैं।' राहुल गांधी ने कहा- "मैंने यह कई बार बताया है, खासकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रदेश के वयस्क नागरिकों की संख्या से कहीं अधिक लोगों ने वोटिंग की। चुनाव आयोग द्वारा शाम 5.30 बजे तक मतदान के आंकड़े जारी किये गये थे। बाद में जो अंतिम आंकड़े प्रदान किये गये उसके अनुसार शाम 5.30 बजे से 7.30 बजे के बीच 65 लाख लोगों ने मतदान किया। ऐसा होना संभव ही नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति को मतदान करने में लगभग 3 मिनट लगते हैं। इस हिसाब से तो सुबह 2 बजे तक मतदाताओं की कतारें लगनी चाहिये थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब कांग्रेस व विपक्ष ने आयोग से वीडियो सबूत मांगे तो उसे न केवल मना कर दिया गया बल्कि आयोग ने कानून ही बदल दिया ताकि विपक्षी दल वीडियोग्राफी के लिए न कह सकें।' गौरतलब है कि राहुल ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान ऐसे वक्त में चुनावी गड़बड़ियों की ओर इशारा किया है जब कुछ ही दिनों पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनके खासमखास दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क ने साफ किया है कि इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। बैलेट पेपर की हिमायत करते हुए मस्क ने तो यहां तक कहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। यानी ये उस आरोप की पुष्टि कर रहे हैं जो भारत के कई विपक्षी दल 2022 से लगा रहे हैं। आरोप है कि पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में वोटिंग मशीनों में बड़े पैमाने पर धांधली कर भाजपा ने दो-चार नहीं वरन लगभग 80 सीटें जीती हैं। इतना ही नहीं, कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी इसी पैटर्न के द्वारा हारती हुई भाजपा ने चंद घंटों में इतनी सीटें जीत लीं कि वह सरकार बनाने में कामयाब हो गयी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के उदाहरण इस सिलसिले में दिये जाते हैं। वैसे तो भारत में जिस तरह से शासकीय मशीनरी के जरिये लोकतंत्र को अपहृत किया गया है और मोदी सरकार निरंकुश तरीके से काम कर रही है, वह दुनिया अब जान चुकी है, राहुल द्वारा जो बातें भारतीय समुदायों के समक्ष कही जा रही हैं, वह दूर तलक जायेंगी क्योंकि वहां का मीडिया उसे तटस्थ होकर जगह देता है जो निश्चित ही भारतीय मीडिया के मुकाबले बहुत अधिक जनतांत्रिक, स्वतंत्र और निष्पक्ष है। भारत का मीडिया विपक्ष की बातों को जहां स्थान नहीं देता वहीं अमेरिकी या लोकतांत्रिक रूप से परिपक्व किसी भी देश का मीडिया सरकार की बजाय प्रतिपक्ष को तरजीह देता है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की बातें एक बार फिर से विश्वपटल पर प्रमुखता से लोगों के सामने आयेंगी। अनुमानों के मुताबिक भाजपा ने राहुल के इस बयान को 'संवैधानिक संस्थाओं का अपमान' बताया तथा राहुल पर 'देश को बदनाम करने की सुपारी' लेने का आरोप लगा दिया है। पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि, 'राहुल गांधी विदेश जाकर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं।' यही उनकी पहचान बन गई है। यह दिखाता है कि कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विरोध करते हुए भारत के विरोध पर उतर गये हैं-वह भी विदेशी धरती पर।' पूनावाला के अनुसार 'पूरी दुनिया भारत के चुनाव आयोग और निर्वाचन प्रणाली की प्रशंसा कर रही है पर भारत के खिलाफ और देश की बदनामी की सुपारी लेने का काम राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम कर रहा है।' इसी तरह संबित पात्रा ने राहुल गांधी के बयान पर नेशनल हेराल्ड मामले में चल रही ईडी की जांच का जिक्र करते हुए कहा कि वे अब जेल जा सकते हैं।

भारतीय मिसाइलों व रक्षा उपकरणों का बज रहा दुनिया में डंका

-मृत्युंजय दीक्षित

> भारत ने ब्रह्मोस सुपर सोनिक मिसाइल की आपूर्ति के लिए जनवरी 2022 में फिलीपींस के साथ 375 मिलियन डालर का समझौता किया था जो कि अब लागू हो चुका है। अप्रैल-2024 फिलीपींस को ब्रह्मोस की पहली खेप मिली। इंडोनेशिया भी भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने वाला है। वियतनाम और मलेशिया जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने भी इस अत्याधुनिक मिसाइल को खरीदने में रुचि दिखाई है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सर्वांगीण विकास के पथ पर बढ़ता हुआ आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। रक्षा क्षेत्र भी इस धारा से अछूता नहीं है इसमें भी अहम और व्यापक परिवर्तन दिख रहा है। 2014 के पूर्व मात्र एक दशक पूर्व तक भारत की पहचान रक्षा उपकरणों के खरीदार की हुआ करती थी। रक्षा खरीद में घोटालों के समाचार आना सामान्य बात थी फिर भी खरीदे गए हथियारों की समय पर आपूर्ति नहीं होती थी।

मोदी जी के नेतृत्व में ये परिस्थितियाँ तीव्रता के साथ बदल रही हैं। अब भारत जल, थल और नभ तीनों सेनाओं के सभी अंगों को सुदृढ़ करने के लिए दिन-रात प्रयास कर रहा है जिससे रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और बल दोनों निरंतर बढ़ रहे हैं। भारत के रक्षा वैज्ञानिक निरंतर शोध में में व्यस्त हैं। हर दिन किसी न किसी मिसाइल का सफल परीक्षण किया जा रहा है, रक्षा उपकरणों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है जिसके फलस्वरूप भारत की मिसाइलों व रक्षा उपकरणों का डंका विश्व बार में बजने लगा है। अब भारत रक्षा उपकरणों तथा तकनीक का क्रेता ही नहीं विक्रेता भी बन रहा है। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के अंतर्गत होने वाले समझौतों में भारत यह बात भी शामिल करता है कि क्रय किये जा रहे हथियारों का निर्माण व सम्बंधित प्रशिक्षण भी भारत में हो। राफेल लड़ाकू विमान इसका प्रमुख उदाहरण है।

आज भारतीय मिसाइलों की क्षमता से विश्व प्रभावित हो रहा है और कई देश भारतीय मिसाइलें खरीदकर उन्हें अपनी सीमाओं की सुरक्षा में लगाना चाहते हैं। वह छोटे देश तथा जिनकी सीमा चीन से लगी हुई है या फिर जिन पर विस्तारवादी चीन की गिद्ध दृष्टि लगी है, विशेष रूप से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदकर अपने यहां तैनात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कुशल रणनीतिकार की तरह चीन व पाकिस्तान को चारों ओर से घेरने का काम कर रहे हैं, जिसमें ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें महत्वपूर्ण हैं। ब्रह्मोस एक ऐसी उन्नत मिसाइल है जिसे न केवल दक्षिण चीन सागर के राष्ट्र अपितु बड़े मुस्लिम राष्ट्र भी खरीद रहे हैं। चीन के शत्रु फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस दी है। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात भारत द्वारा किसी भी देश के साथ किया गया अब तक का सबसे बड़ा रक्षा विक्रय समझौता है।

भारत ने ब्रह्मोस सुपर सोनिक मिसाइल की आपूर्ति के लिए जनवरी 2022 में फिलीपींस के साथ 375 मिलियन डालर का समझौता किया था जो कि अब लागू हो चुका है। अप्रैल- 2024 फिलीपींस को ब्रह्मोस की पहली खेप मिली। इंडोनेशिया भी भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने वाला है। वियतनाम और मलेशिया जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने भी इस अत्याधुनिक मिसाइल को खरीदने में रुचि दिखाई है।

आगामी दिनों में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी ब्रह्मोस मिसाइल के बड़े खरीददार बन सकते हैं। श्रीलंका जैसे छोटे देश जिनकी सीमा चीन से मिलती है उन सभी देशों के साथ ब्रह्मोस को तैनात करने के लिए बातचीत चल रही है। साथ ही यह वर्ष ब्रह्मोस मिसाइल का 25वां वर्ष मनाया जा रहा है इसलिए 25 देशों के साथ ब्रह्मोस की डील को लेकर वार्ता चल रही है जिसमें कुछ देशों के साथ वार्ता अंतिम चरण में पहंच चुकी है।

ब्रह्मोस की विषेषता-सबसे तेज सुपरसेनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भूमि, वायु, जल यानि समुद्र की गहराइयों में भी पलक झपकते ही शत्रु को निशाना बना लेती है। 12 जून 2001 को मिसाइल ने अपनी पहली सफल उड़ान भरी थी। यह भारत और रूस की एक संयुक्त परियोजना है जिस पर लगातार काम चल रहा है। इस मिसाइल का नामकरण भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और मास्को की नदी मोसक्वा के नाम पर किया गया है। 24 जनवरी 2024 के ब्रह्मोस के नये उन्नत वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल की रेंज को बढ़ाया गया है और साथ ही तकनीक को भी बेहतर बनाया गया है। यह मिसाइल अपनी सटीकता के लिए जानी जाती है। अब इस मिसाइल की रेंज बढ़कर 800 किमी हो गई है जबकि पहले रेंज केवल 200 किमी तक ही सीमित थी। यह हवा में ही रास्ता बदलने तथा चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त करने में सक्षम है। यह 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम हैं। यह एक ऐसी मिसाइल है जिसे शत्रु अपने रडार से देख नहीं पायेगा। यह मिसाइल 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है जो किसी भी बड़े टारगेट को पलक झपकते ही ध्वस्त कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय नौसेना के कई युद्धपोतों पर तैनात है।

ब्रह्मोस मिसाइल के बाद भारत के कई अन्य हथियार भी विदेशी की सेनाओं में होंगे जिसमें आकाश मिसाइल, अर्जुन टैंक, लाइट एयरक्राफ्ट जैसे कई उपकरण शामिल हैं जिनके निर्यात करने की तैयारियां चल रही हैं।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

सर्वोच्च न्यायालय का वक्फ कानून पर सबको खुश करने वाला अंतरिम आदेश

-के रवींद्रन

> समान रूप से महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि न्यायालय ने संशोधित कानून के संचालन पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन मुकदमे के लंबित रहने के दौरान यथास्थिति में इस तरह से बदलाव न करने की चेतावनी दी, जिससे किसी भी पक्ष के अधिकारों को नुकसान पहुंचे। यह दोहरा उद्देश्य पूरा करता है। ये कानूनी चुनौती को निरर्थक बना सकते हैं

विवादास्पद वक्फ संशोधन अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश ने विरोधी खेमों के बीच एक असामान्य संतुलन पैदा कर दिया है, जो निर्णायक हस्तक्षेप के बजाय एक सुनियोजित संतुलनकारी कार्य का संकेत देता है। हालांकि यह आदेश संशोधनों के कार्यान्वयन पर पूर्ण रोक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन यह न्यायिक संयम की एक परत पेश करता है जो आश्वस्त और अस्थिर दोनों है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस पक्ष में है। यह कानूनी युद्ध के मैदान को खुला छोड़ देता है, लेकिन संकेत- हालांकि कमजोर- सरकार की स्थिति के अंतिम समेकन की ओर इशारा करते हैं।

सरकार को यथास्थिति बनाये रखते हुए अधिक मजबूत तर्क प्रस्तुत करने का समय देकर, न्यायालय ने अधिक गहन जांच के लिए मंच तैयार किया है जो अंततः विचाराधीन संशोधनों को वैध बना सकता है। सरकार के दृष्टिकोण से, यह अंतरिम व्यवस्था न केवल स्वीकार्य है-परन्तु उसके लिए लाभप्रद भी है। यह मौजूदा कानूनी ढांचे में ठोस खामियों को प्रदर्शित करके बहस को सैद्धांतिक से अनुभवजन्य में बदलने की अनुमति देता है।

पूरे गांवों को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित किये जाने की रिपोर्ट, अक्सर निवासियों की जानकारी या सहमति के बिना, निराशा की एक लहर पैदा करती है जिसे सरकार न्यायालय के समक्ष बढ़ाना चाहती है। इस मुद्दे को सामूहिक वंचितता और प्रणालीगत अस्पष्टता के रूप में प्रस्तुत करके, सरकार न केवल प्रशासनिक आवश्यकता, बल्कि सामाजिक न्याय की कहानी गढ़ रही है। फिर महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कहानी एक ऐसी अदालत के साथ प्रतिध्वनित होने की संभावना है जिसने पिछले फैसलों में कानून की सिद्धांतवादी व्याख्याओं पर संतुलन और व्यावहारिकता की ओर झुकाव दिखाया है।

समान रूप से महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि न्यायालय ने संशोधित कानून के संचालन पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन मुकदमे के लंबित रहने के दौरान यथास्थिति में इस तरह से बदलाव न करने की चेतावनी दी, जिससे किसी भी पक्ष के अधिकारों को नुकसान पहुंचे। यह दोहरा उद्देश्य पूरा करता है। ये कानूनी चुनौती को निरर्थक बना सकते हैं। लेकिन सरकार के लिए, यह अभी भी अपना मामला बनाने, डेटा एकत्र करने और पिछली व्यवस्था के तहत लंबे समय से चले आ रहे अन्याय के लिए आवश्यक सुधार के रूप में संशोधन को तैयार करने का रास्ता खुला छोड़ता है। न्यायालय के निर्देश के शब्द ही कठोर अंतरिम कदम उठाने की अनिच्छा को दशार्ते हैं, जो अंतिम फैसले के समय उसके हाथ बांध सकते हैं। इस स्थिति से जो उभरता है, वह एक तरह की न्यायिक हेजिंग है- चुनौती देने वालों को उम्मीद देने के लिए पर्याप्त अस्पष्टता, लेकिन सरकार के लिए पैंतरेबाजी करने के लिए पर्याप्त जगह। चुनौती देने वालों को निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा की गयी कुछ टिप्पणियों से सांत्वना मिली है, जो संशोधनों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित लोगों के अधिकारों के लिए कुछ हद तक सहानुभूति का संकेत देती हैं। लेकिन यह सांत्वना अंततः वास्तविक से ज्यादा बयानबाजी साबित हो सकती है। न्यायालय का इतिहास बताता है कि जब तक विचाराधीन कानून स्पष्ट रूप से असंवैधानिक या घोर अन्यायपूर्ण न हो, तब तक यह विधायी और कार्यकारी शाखाओं के अधीन रहता है, खासकर जब व्यापक शासन संबंधी मुद्दे शामिल हों।

क्रिश्चियन एलायंस और एसोसिएशन ऑफ सोशल एक्शन जैसे नये हस्तक्षेपकताओं के साथ सरकार का रणनीतिक गठबंधन इसके हाथ को और मजबूत करता है। इन समूहों का तर्क है कि पिछले कानून को धार्मिक या संस्थागत दावों के तहत व्यक्तियों- अक्सर अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से- को उनके वैध संपत्ति अधिकारों से वंचित करने के लिए हथियार बनाया गया था। ऐसी आवाजों को एकजुट करके, सरकार कानून को बहुसंख्यकवादी थोपे जाने के रूप में नहीं, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष, समावेशी सुधार के रूप में फिर से परिभाषित कर रही है। यह पुनर्स्थापन महत्वपूर्ण है। यह मुद्दे को एक संकीर्ण प्रशासनिक बदलाव से संपत्ति के अधिकारों को बहाल करने और ऐतिहासिक असंतुलन को ठीक करने के लिए एक नैतिक धर्मयुद्ध में बदल देता है। न्यायपालिका, जब इस तरह के नैतिक ढांचे का सामना करती है- खासकर अगर वास्तविक जीवन की गवाही और आंकड़ों से इसकी पुष्टि होती है - अक्सर विधायी इरादे को बनाये रखने की ओर झुक जाती है जब तक कि एक मजबूत संवैधानिक उल्लंघन साबित न हो जाये।

नये कानून के तहत प्रक्रियात्मक चिंताएं या कथित अतिक्रमण के उदाहरण भी इसे अमान्य करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं जब तक कि मनमानी या लक्षित भेदभाव का एक स्पष्ट पैटर्न नहीं दिखाया जा सकता है। अब तक, चुनौती देने वालों ने वास्तविक नुकसान के प्रलेखित मामलों के बजाय संभावित दुरुपयोग के जोखिम पर अधिक ध्यान दिया है। इसके विपरीत, सरकार मौजूदा प्रणाली की विफलताओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो पहले से ही मूर्त और प्रदर्शन योग्य हैं। साक्ष्य की गुणवत्ता और प्रकृति में यह विषमता अंतिम निर्णय में भारी पड़ सकती है।

इसके अलावा, अदालत की अंतरिम टिप्पणियों की भाषा संभावित जटिलताओं के बारे में गहरी जागरूकता का सुझाव देती है जो विधायी प्रक्रिया में समय से पहले हस्तक्षेप करने से उत्पन्न हो सकती हैं। इस बात पर जोर देकर कि मामले के लंबित रहने के दौरान कोई नयी जटिलताएं पेश नहीं की जानी चाहिए, अदालत समय खरीदती हुई प्रतीत होती है - न कि समय पर निर्णय लेने के लिए कानून के बारे में बात करना और बिना व्यवधान पैदा किए निष्पक्ष सुनवाई करना। यह सतर्क दृष्टिकोण, तटस्थ प्रतीत होते हुए भी, अक्सर यथास्थिति या इस मामले में, नये पेश किये गये परिवर्तनों के पक्ष में काम करता है। एक बार जब कोई कानून व्यवस्था में स्थापित हो जाता है - यहां तक कि एक अंतिम क्षमता में भी- तो इसे उलटना संस्थागत रूप से अधिक कठिन हो जाता है जब तक कि ऐसा करने के लिए कोई भारी कारण न हो। इसके अतिरिक्त, संशोधनों का समर्थन करने वाली आवाजों की बढ़ती संख्या से न्यायालय के प्रभावित होने की संभावना है, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों और सामाजिक वकालत समूहों से। ये हितधारक अपने साथ एक हद तक नैतिक और सामाजिक-राजनीतिक वैधता लाते हैं जिसे नजरंदाज करना मुश्किल है। कानूनों के पिछले शासन के तहत बहिष्कार और बेदखली के उनके आख्यान एक भावनात्मक और मानवीय आयाम पेश करते हैं जो अन्यथा एक अमूर्त कानूनी प्रतियोगिता हो सकती है। यदि चुनौती देने वाले तुलनात्मक रूप से सम्मोहक प्रति-कथा प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं-जो कानूनी तकनीकों से परे हो और न्याय को एक आंतरिक तरीके से संबोधित करे-तो पेंडुलम सरकार के पक्ष में झूलता रहेगा।

जयंती

राजकुमार (दक्षिण भारतीय अभिनेता)

राजकुमार का जन्म 24 अप्रैल, 1928 को मद्रास में हुआ था। राजकुमार को राष्ट्रीय स्तर पर कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। वर्ष 1995 में राजकुमार को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहब फालके पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1983 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। 12 अप्रैल 2006 को बंगलोर में कन्नड़ फिल्मों के इस महानायक का निधन हो गया। राजकुमार दक्षिण भारतीय सिनेमा के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले कन्नड़ फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे। अतः इन्हें कन्नड़ फि ल्मों का सबसे महान नायक कहा जाए तो यह कदापि गलत नहीं होगा।

पुण्यतिथि

रामधारी सिंह 'दिनकर'

जन्म: 23 सितंबर, 1908, बिहार; मृत्यु: 24 अप्रैल, 1974, तमिलनाडु) हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक, कवि एवं निबंधकार थे। 'राष्ट्रकवि दिनकर' आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। उनको राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत, क्रांतिपूर्ण संघर्ष की प्रेरणा देने वाली ओजस्वी कविताओं के कारण असीम लोकप्रियता मिली। दिनकर जी ने इतिहास, दर्शनशास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से की। साहित्य के रूप में उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। दिनकर के पिता एक साधारण किसान थे। दिनकर दो वर्ष के थे, जब उनके पिता का देहावसान हो गया। परिणामत: दिनकर और उनके भाई-बहनों का पालन-पोषण उनकी विधवा माता ने किया। दिनकर का बचपन और कैशोर्य देहात में बीता, जहाँ दूर तक फैले खेतों की हरियाली, बांसों के झुरमुट, आमों के बगीचे और कांस के विस्तार थे। प्रकृति की इस सुषमा का प्रभाव दिनकर के मन में बस गया, पर शायद इसीलिए वास्तविक जीवन की कठोरताओं का भी अधिक गहरा प्रभाव पड़ा।

कल मिलेंगे

एक बार जब मैं ट्रेन में सफर कर रहा था तो सामने बैठी एक आंटी ने मुझसे पूछा- कहां के हो बेटा?

मैंने कहा-मेरी शादी हो गई है आंटी, अब मैं कहीं का नहीं रहा.

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।

RNI No. : DELHIN/2016/70240

Phone No.: 9871221635

E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com

(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

खेल/विदेश/कारोबार/फिल्म

गाजा में इजराइली हमले में 23 लोगों की मौत

(एजेन्सी)।

गाजा। गाजा शहर में एक स्कूल पर रात में हुए इजराइली हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। जिस स्कूल पर इजराइल ने हमला किया, उसमें लोगों ने शरण ली हुई थी। इस बीच अरब मध्यस्थ, हमास के साथ युद्ध को समाप्त करने के प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं। प्रस्ताव में पांच से सात वर्ष का संघर्ष विराम और सभी शेष बंधकों की रिहाई शामिल है। इस हमले पर इजराइल की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। हमले में कई टेंटों में आग लग गई, जिससे लोग जिंदा जल गए।

सेना का कहना है कि वह केवल आतंकवादियों को निशाना बनाती है और नागरिकों की मौत के लिए हमास जिम्मेदार है क्योंकि उसके लड़ाके घनी आबादी वाले इलाकों में छिपे हुए हैं। इस बीच फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने कहा कि गाजा में खाद्य पदार्थों सहित सभी आयातों पर इजराइल की सात सप्ताह लंबी नाकेबंदी असहनीय है। फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने युद्ध जारी रखने के इजराइल के बहाने खत्म करने के लिए हमास से बंधकों को रिहा करने का आह्वान किया। उन्होंने एक भाषण के दौरान कठोर का इस्तेमाल करते हुए हमास से हथियार छोड़ने का आह्वान करते हुए अपनी मांगों को दोहराया। मिस्र और हमास के अधिकारियों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि मिस्र और कतर अब भी युद्ध विराम प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसमें पूरे क्षेत्र से इजराइली सेना की वापसी और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है। युद्ध विराम वार्ता में शामिल रहे ट्रंप प्रशासन ने कहा कि वह इजराइल के रुख का पूर्ण समर्थन करता है।

न्यूजर्सी के जंगल में लगी आग, हजारों लोगों को घर खाली करने पड़े

(एजेन्सी)।

न्यूजर्सी। न्यूजर्सी में तेजी से फैल रही जंगल की आग के कारण बुधवार को हजारों लोगों को अपने घरों को खाली करना पड़ा। इसके चलते एक प्रमुख राजमार्ग के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। न्यू जर्सी के सबसे व्यस्त राजमार्गों में से एक गार्डन स्टेट पार्कवे को मंगलवार रात बानेगेंट और लेसी टाउनशिप के बीच बंद कर दिया गया था। ओशन काउंटी शेरिफ कार्यालय ने बुधवार सुबह पोस्ट किया कि इसे फिर से खोल दिया गया है। न्यू जर्सी फॉरेस्ट फायर सर्विस ने बताया कि 1,300 से अधिक इमारतों को खतरा है और लगभग तीन हजार लोगों को अन्यत्र भेजा गया है। बानेगेंट पुलिस विभाग के अनुसार, दो स्कूलों में आश्रय स्थल खुले हैं। जर्सी सेंट्रल पावर एंड लाइट कंपनी ने मंगलवार शाम फॉरेस्ट फायर सर्विस के अनुरोध पर लगभग 25 हजार उपभोक्ताओं की बिजली काट दी, जिसमें बानेगेंट टाउनशिप के हजारों उपभोक्ता भी शामिल हैं। कंपनी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि बुधवार से पहले बिजली बहाल होने की उम्मीद नहीं है।

पोप फ्रांसिस के निधन पर हमास ने चौंकाया, जारी किया बयान

(एजेन्सी)।

दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक नेता पोप फ्रांसि का 21 अप्रैल को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके स्मृति में भारत ने तीन दिवसीय राजकीय शोक का ऐलान किया है। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद देश दुनिया से प्रतिक्रिया आईं, सभी ने शोक जताया। लेकिन इसी बीच कैथोलिक पोप के निधन पर हमास का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है। पोप के अंतिम भाषण में मध्य पूर्व के ईसाइयों को दिए गए संदेश के बाद हमास का बयान सामने आया है। पोप फ्रांसिस के निधन के कुछ घंटों बाद हमास ने चर्च से कहा कि इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन (हमास) वेटिकन के पोप फ्रांसिस के निधन पर वैश्विक कैथोलिक चर्च और सभी ईसाइयों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सच्ची सहानुभूति व्यक्त करता है, जिनका जीवन मानवीय और धार्मिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए समर्पित था।

हमास ने कहा कि पोप फ्रांसिस ने अंतर-धार्मिक संवाद के मूल्यों को बढ़ावा पोप फ्रांसिस ने अंतर-धार्मिक संवाद के मूल्यों को बढ़ावा देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई और लोगों के बीच आपसी समझ और शांति का आह्वान किया। नफरत और नस्लवाद को खारिज किया। उन्होंने लगातार आक्रामकता और युद्ध का विरोध किया और गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ किए गए युद्ध अपराधों और नरसंहार के कृत्यों की निंदा करने में एक प्रमुख धार्मिक आवाज थे। इसी क्रम में एक मुल्क ऐसा भी है जिसने पोप फ्रांसिस के निधन के बाद एक पोस्ट किया और फिर उसे तुरंत डिलीट भी कर दिया। लेकिन हाईटेक हो चुकी दुनिया में वो उसे सुर्खियां बटोरने से नहीं रोक सके। ये मुल्क इजरायल है। दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोप फ्रांसिस की मृत्यु के बाद इजरायल द्वारा शोक संदेश पोस्ट किया गया और पोस्ट किए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर इसे हटा दिया गया। अधिकारियों ने बाद में गलती से किया गया पोस्ट बताया। इसे हटाने का कारण गाजा में इजरायल की कार्रवाइयों की पोप की मुखर निंदा बताया गया।

पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को हो रहा फायदा: पंत

(एजेन्सी)।

लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के कप्तान ऋषभ पंत ने इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच में मंगलवार को यहां दिल्ली कैपिटल्स से आठ विकेट की शिकस्त झेलने के बादे कहा कि इस मैदान पर पहले गेंदबाजी करने वाली टीम फायदे में रह रही है।

लखनऊ के छह विकेट पर 159 रन के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 13 गेंद शेष रहते दो विकेट पर 161 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। पंत ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में प्रसारकों से कहा, यहां टॉस ने अहम भूमिका निभाई है।

पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को पिच से काफी मदद मिल रही है। लखनऊ में खैर ऐसा ही होता है, मैच आगे बढ़ने के साथ पिच बल्लेबाजी के लिए आसान होती जाती है। उन्होंने कहा, मैच इसी तरह चलता है और आप शिकायत नहीं कर सकते, दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान हो जाती है। टॉस एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, लेकिन हम बहाने नहीं ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें पता था कि हमने 20 रन कम बनाये है।

खुद बल्लेबाजी के लिए सातवें क्रम पर आने के बाद आलोचना झेल रहे इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा, हम परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहते थे। हमने (अब्दुल) समद को ऐसी पिच का फायदा उठाने के लिए भेजा था। (डेविड) मिलर के क्रीज पर जाने के बाद हमारी रन गति आगे नहीं बढ़ सकी। हमें इन चीजों को देखते हुए सर्वश्रेष्ठ संयोजन बनाना होगा।

2026 में 6.3 फीसदी रहेगी भारत की विकास दर!

(एजेन्सी)।

नई दिल्ली। आईएमएफ के बाद अब वर्ल्ड बैंक ने भारत का अनुमानित ग्रोथ रेट घटा दिया है। वर्ल्ड बैंक ने भारत का अनुमानित ग्रोथ रेट 6.7 फीसदी से घटाकर 6.3 फीसदी कर दिया है। ये ग्रोथ रेट वित्त वर्ष 2025-26 की रहने वाली है। इस ग्रोथ रेट के बारे में साउथ एशिया डेवलपमेंट रिपोर्ट Taxing Times में बताया गया है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ग्रोथ रेट 6.5 फीसदी माना गया था। वहीं इस वित्त वर्ष पहले ये ग्रोथ रेट 6.7 फीसदी माना गया था। जिसे अब रिपोर्ट में घटा दिया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत का नया अनुमानित ग्रोथ रेट 6.3 फीसदी होने वाला है। ये ध्यान देने वाली है कि ये विकास अनुमान ऐसे समय में घटाया गया है, जब पूरे विश्व में अमेरिका और चीन के बीच हो रहे विवाद के कारण अनिश्चितता बनी हुई है। इन दोनों के बीच लंबे समय से टैरिफ वार चल रही है। अप्रैल 2 की रात अमेरिका भारत सहित 60 देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा करी थी। जिसका मतलब अब अमेरिका में सामान या वस्तु निर्यात करने के लिए टैरिफ के रूप में टैक्स दिया जाएगा।

हालांकि ये टैरिफ अब 90 दिनों के लिए रोक दिया गया है। इसमें चीन शामिल नहीं है। जिसके बाद से चीन और अमेरिका के बीच विवाद बना हुआ है। साउथ एशिया डेवलपमेंट रिपोर्ट Taxng Times के अनुसार भारत के आर्थिक विकास में गिरावट आई है। क्योंकि हम सार्वजनिक पूंजी निवेश, नीतिगत अनिश्चितता और ग्लोबल आर्थिक कमजोर में उम्मीद से कम विकास कर पाए है। जिसके कारण अनुमानित विकास दर में गिरावट आई है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी भारत का अनुमानित विकास दर 6.5 फीसदी से घटाकर 6.2 फीसदी कर दिया है।

इमरान हाशमी निभाएंगे एक और असल जिंदगी का किरदार

(एजेन्सी)। बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ग्राउंड जीरो को लेकर चर्चा है। अब इस बज के साथ साथ एक और बड़ी खबर आ रही हैं। अभिनेता यामी गौतम और इमरान हाशमी ने भारत की सबसे महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाइयों में से एक, 1985 के शाह बानो मामले से प्रेरित अपने आगामी ऐतिहासिक फैसले की शूटिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इस बहुप्रतीक्षित फिल्म में, यामी शाह बानो की भूमिका में हैं, जबकि इमरान उनके पूर्व पति अहमद खान से प्रेरित एक किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का उद्देश्य एक ऐसे ऐतिहासिक मामले पर प्रकाश डालना है जिसने लैंगिक अधिकारों, धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों और संवैधानिक न्याय पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। यह केस भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष को दिखाएगा। सूत्रों के मुताबिक, मेकर्स ने इस फिल्म में यामी गौतम के पति की भूमिका निभाने के लिए इमरान हाशमी को चुना है। वह फिल्म में अहमद खान की भूमिका में नजर आएंगे। रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म की शूटिंग का पहला शेड्यूल भी पूरा हो चुका है। फिल्म में 1970 का समय दिखाया जाएगा और यामी गौतम मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती नजर आएंगी। 1978 में पांच बच्चों की मां 62 वर्षीय शाहबानो को उनके वकील पति मोहम्मद अहमद खान ने तीन तलाक दे दिया था। जब उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांगा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 1985 में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि धारा 125 सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होती है और तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। यह फैसला ऐतिहासिक था, जिसने लैंगिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष संविधान के सिद्धांतों को मजबूत किया। वर्क फ्रंट की बात करें तो यामी गौतम आखिरी बार धूम धाम और आर्टिकल 370 में नजर आई थीं। आर्टिकल 370 में यामी गौतम की एक्टिंग ने लोगों को काफी प्रभावित किया था। वहीं दूसरी तरफ इमरान हाशमी इन दिनों अपनी फिल्म ग्राउंड जीरो के प्रमोशन में व्यस्त हैं। यह फिल्म भी एक सच्ची घटना पर आधारित है और वे फिल्म में बीएसएफ ऑफिसर की भूमिका में नजर आएंगे। ग्राउंड जीरो के बाद एक बार फिर इमरान आने वाली फिल्मों में असल जिंदगी का किरदार निभाते नजर आएंगे। बता दें कि वह सलमान खान की फिल्म 'टाइगर जिंदा है' में नजर आए थे।

महिला संवाद में योजनाओं की दी जा रही जानकारी

महिलाओं की समस्याओं एवं आकांक्षाओं को मोबाइल एप में किया जा रहा है दर्ज

एसबी ब्यूरो प्रमुख/मृगांक शेखर सिंह

जमुई। राज्य के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम संगठन स्तर पर राज्य के सभी जिलों में महिला संवाद आयोजित किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार 23 अप्रैल को जमुई जिले में जीविका द्वारा संपोषित कुल 22 ग्राम संगठनों में महिला संवाद कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जिले में इतनी भीषण गर्मी के बावजूद महिलाओं का उत्साह कम नहीं हुआ कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं और संवाद रथ में चलित विडियो देखकर योजनाओं के बारे में जाना और समझा। कार्यक्रम में पंचायत आयोजन दल के साथ दसों प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में जीविका कर्मी संवाद स्थल पर मौजूद रहे।

चकाई प्रखंड के चन्द्रमनडीह पंचायत के योगीडीह गाँव एवं चकाई पंचायत के अंडीडीह गाँव में सुबह के समय पहली पाली में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में 500 से ज्यादा महिलायें शामिल हुईं और योजनाओं का लाभ उठाया। योगीडीह गाँव में मुद्रिका देवी, चंचला देवी के अलावा अन्य महिलाओं ने सामूहिक रूप से पुस्तकालय, पक्की सड़क और नाला, सोलर लाईट बनाने की मांग को उठायो साथ ही वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन की राशि बढाने की बात कही।

चकाई प्रखंड के प्राची पंचायत के नावाडीह गाँव वार्ड नंबर 4 स्थित पंचायत भवन परिसर में आयोजित दूसरी पाली में माँ शीतला ग्राम संगठन में आयोजित संवाद कार्यक्रम में 200 से ज्यादा

महिलाएं शामिल हुईं। कार्यक्रम की शुरुआत में महिला संवाद के उद्देश्य पर चर्चा की गई। ततपश्चात 45 मिनट का विडियो दिखाया गया, जिसमें बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्रियान्वित महत्वकांक्षी योजनाओं को दिखाया गया। संवाद कार्यक्रम में बिहार सरकार की योजनाओं से समाहित लीफलेट एवं मुख्यमंत्री सन्देश पत्र का वितरण किया गया। इस दौरान महिलाओं को मुख्यमंत्री का सन्देश पत्र पढ़कर भी सुनाया गया। बजरंग बली स्वयं सहायता समूह की सचिव ललिता देवी ने बताया कि जीविका से जुड़कर उसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। आज वह न सिर्फ डायटीशियन का कोर्स की है बल्कि हाल ही में वह चकाई प्रखंड मे अपना थेरेपी सेन्टर भी चलाती है। वहीं अन्य महिलाओं ने खराब सड़क एवं खराब चापाकल के कारण पानी की किल्लत को सामूहिक रूप से उठाया।

महिलाओं के द्वारा बताई गई समस्याओं एवं आकांक्षाओं को नोट कर मोबाइल एप में सम्बन्धित कर्मियों के द्वारा दर्ज किया गया, जिसे सम्बन्धित विभाग कब पास भेज जाएगा।

उल्लेखनीय है की 18 अप्रैल 2024 से ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा राज्य के सभी जिलों में महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जमुई जिले में कुल 1245 ग्राम संगठनों में महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन 14 जून तक किया जायेगा। संवाद कार्यक्रम में दौरान बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्रियान्वित महत्वकांक्षी योजनाओं, जिसमें महिला के लिए आरक्षण, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), नशामुक्ति अभियान, बाल-विवाह, दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान, मुख्यमंत्री मेधावृति योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना से सम्बंधित जानकारी महिलाओं को विडियो के माध्यम से दी जा रही है।

इस संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य की विकास योजनाओं के नीति निर्धारण में महिलाओं की अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं को स्थान मिले।

भाजपा कार्यालय में वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव मनाया गया

संजना भारती संवाददाता

सिवान। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, सिवान पूर्वी में वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव मनाया गया। 1857 की क्रांति के इस महानायक को श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हुए उनके बलिदान और साहस को स्मरण किया गया।

इस अवसर पर भाजपा जिला संगठन के कई सम्मानित पदाधिकारीगण उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से जिला महामंत्री अवधेश पांडेय, प्रमोद तिवारी, कालीचरण प्रजापति उपाध्यक्ष जितेन्द्र सिंह, सुजीत पांडेय, जगन राम मंत्री अखिलानंद सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह कोषाध्यक्ष संतोष कुमार उर्फ कनवर लाल जिला कार्यालय मंत्री पुष्पेन्द्र बाबा प्रवक्ता दिलीप सिंह मंडल अध्यक्षगण अमरनाथ शर्मा (बसंतपुर), सत्येन्द्र सिंह (लकड़ी पूर्वी), मृत्युंजय सिंह (लकड़ी पश्चिम), दिवाकर दुबे (भगवानपुर मध्य), गिरीशदेव सिंह (भगवानपुर पश्चिम) मंडल महामंत्री नवल किशोर सिंह तथा भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता-यशवंत सिंह, रामकुमार सिंह, प्रेम रंजन सिंह, बृजेश सिंह सहित अन्य भी उपस्थित रहे।

शौर्य, स्वाभिमान और संगठन की हुंकार

बाबू वीर कुँवर सिंह शौर्य दिवस पर पटना में गूँजा 'जय सांगा' का उद्घोष

पटना से संजना भारती स्थानीय संपादक राकेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

पटना। बाबू वीर कुँवर सिंह शौर्य दिवस के अवसर पर राजधानी पटना के बापू सभागार में शौर्य, स्वाभिमान और संगठन की त्रिधारा फूट पड़ी। क्षत्रिय समाज द्वारा आयोजित इस विराट समारोह में सारण सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि यह भीड़ नहीं, यह चेतना है; यह सभा नहीं, यह उद्घोष है।

श्री राजीव प्रताप रूडी इस समारोह के मुख्य अतिथि थे, जिनके प्रयासों से भारतीय वायुसेना के सूर्यकिरण और आकाशगंगा टीम के लड़ाकू विमानों ने गगनभेदी गर्जना के साथ बाबू वीर कुँवर सिंह को आकाश से ऐतिहासिक सलामी अर्पित की।

कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री श्री सुमित सिंह, पूर्व मंत्री श्री नीरज कुमार सिंह श्बबलूश, विधायक श्री राजेश सिंह, विधायक कु. श्रेयसी सिंह, पूर्व विधायक श्रीमती स्वर्णा सिंह और श्री विनय कुमार सिंह, भाजपा नेता श्री संजय सिंह श्टाइगरश, जदयू नेता श्री अजय सिंह (सिवान), श्रीमती निवेदिता सिंह, श्री चंद्र विजय सिंह, श्री बिट्टू सिंह, श्री व्यास सिंह, श्री रितेश सिंह, श्री गोपाल शरण सिंह, श्री यशवंत सिंह, श्री मनोरंज सिंह, श्री मनोज सिंह, बाबू वीर कुँवर सिंह शौर्य दिवस आयोजन समिति के संरक्षक पद्मश्री डॉ. आर.एन. सिंह तथा संयोजक श्री ब्रजेश सिंह सहित राज्य के विभिन्न जिलों से पधारे क्षत्रिय समाज के हजारों गणमान्य जन उपस्थित थे। इससे पूर्व गंगा तट पर भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण और आकाशगंगा टीमों ने अद्भुत और अविस्मरणीय प्रदर्शन कर आकाश में शौर्य की अमिट छाप छोड़ी। जब भारतीय सैनिक 20,000 फीट की ऊँचाई से तिरंगा लेकर उतरे और वीर बाबू कुँवर सिंह की छवि आकाश में लहराई, तो लगा जैसे इतिहास पुनः सजीव हो उठा है।

श्री रूडी ने अपने भावनात्मक संबोधन की शुरूआत पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए की और कहा कि भारत की धरती पर कायरता का कोई स्थान नहीं। वीरों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने मंच से उद्घोष किया कि अब क्षत्रिय समाज अपनी पहचान, गरिमा और सम्मान की पुनर्स्थापना के लिए एकजुट होगा। श्री रूडी ने कहा कि "जय श्रीराम" और "जय भवानी" के साथ अब नया उद्घोष होगा 'जय सांगा!' यह केवल नारा नहीं, बल्कि नवचेतना का सिंहनाद है।

श्री रूडी ने कहा कि बिहार के हर गाँव में एक पीपल, एक मिट्टी का ढेर, एक धागा और एक संकल्प जन्म लेता है, जो कालांतर में मंदिर बनता है-ठीक वैसे ही अब समाज को भी अपनी पहचान की नींव रखनी है। उन्होंने भावपूर्ण शब्दों में कहा कि हम सीढ़ी हैं, लोग चढ़ते हैं और लात मार देते हैं। अब नहीं। अब हम उस अगली पीढ़ी के लिए पुल बनेंगे, जिन्हें मंज़िल तक जाना है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अब से सांसद नियंत्रण कक्ष बिहार के क्षत्रिय समाज के लिए 24 घंटे सहायता केंद्र के रूप में कार्य करेगा। किसी भी संकट, आपदा या जरूरत के समय समाज को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा।

डॉ. आर.एन. सिंह के अध्यक्षता में आयोजित इस भव्य समारोह में प्रदेश भर से आए युवाओं, महिलाओं और समाज के वरिष्ठ जनों ने अभूतपूर्व उत्साह के साथ भाग लिया। रूडी ने इसे 1999 में दिल्ली के आयोजन की पुनरावृत्ति बताया, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मंच से आशीर्वाद दिया था।

अपने ओजस्वी अंदाज में रूडी ने सभा का आह्वान करते हुए कहा कि अब मांगने का नहीं, दिशा देने का समय है। अब मौन रहने का नहीं, जय सांगा के स्वर में समाज को पुकारने का वक्त है। कार्यक्रम का समापन वीर बाबू कुँवर सिंह, महाराणा प्रताप और राणा सांगा के जयघोष के साथ हुआ। शौर्य का यह महायज्ञ पटना की धरती पर क्षत्रिय चेतना के नवप्रभात का प्रतीक बन गया।

न्यायिक कार्य से विरत रहे अधिवक्ता, डीएम का किया घेराव

अधिवक्ताओं ने सौंपा मांग पत्र

संयुक्त पुलिस आयुक्त राजेश कुमार सिंह वार्ता करते हुए अधिवक्तागण.(छायाः एसबी)

एसबी संवाददाता

वाराणसी। बुधवार को सेन्ट्रल बार एसोसिएशन व बनारस बार एसोसिएशन के संयुक्त साधारण सभा के बैठक में प्रस्तावक वासुदेव पटेल, अनुप सिंह, कन्हैया पटेल, माधव पाण्डेय के प्रस्ताव पर अधिवक्ता सम्पूर्ण दिवस न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किये तथा मंगलेश दुबे व राजेश गुप्ता के नेतृत्व में सिविल कोर्ट में जुलूस निकालकर चक्रमण करते हुए रायफल क्लब में जिलाधिकारी का घेराव कर मांग पत्र दिये।

मांग पत्र में अधिवक्ता पुत्र की हत्या के निष्पक्ष विवेचना कराने व घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग। पीडित अधिवक्ता परिवार को एक करोड रुपया प्रदेश सरकार मुआवजा, शिवपुर थानाध्यक्ष को लंबित करने आदि की मांग की।

जुलूस व घेराव में मंगलेश दूबे, राजेश गुप्ता, सतीश तिवारी, शशांक श्रीवास्तव, वासुदेव पटेल, अनुप सिंह, कन्हैया पटेल, माधव पाण्डेय, रंजन मिश्रा, अविनाश गुप्ता, सोविन वर्मा, विशाल मौर्या, रविन्द्र यादव, विवेक शंकर, गौतम कुमार झा, सत्यप्रकाश सिंह सुनील, दीपक राय कान्हा, संजय सिंह, आशीष सिंह समेत सैकड़ों अधिवक्ता सम्मिलित रहे।

पंजाब के शहरों को कूड़ा-मुक्त बनाना प्रदेश सरकार का मुख्य लक्ष्यः डॉ. रवजोत सिंह

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। पंजाब के शहरों को कूड़ा-मुक्त बनाना प्रदेश सरकार का मुख्य लक्ष्य है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जहां शहरी नागरिकों के सहयोग की आवश्यकता है, वहीं सफाई सेवकों और सीवरमैनों के सहयोग की भी जरूरत है।

पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने आज म्यूनिसिपल भवन में सफाई सेवक, सीवरमैन और फायर ब्रिगेड यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

उन्होंने सफाई सेवकों, सीवरमैनों और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए उन्हें विभाग की रीढ़ की हड्डी बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार सफाई सेवकों, सीवरमैनों और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों समेत समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सफाई सेवकों और सीवरमैनों की भलाई को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा।

यूनियन प्रतिनिधियों की मांगों को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि पंजाब के विभिन्न शहरों में सफाई सेवकों, सीवरमैनों और फायर ब्रिगेड की सेवा निभा रहे कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और उनकी जायज मांगों का समयबद्ध तरीके से शीघ्र हल किया जाएगा।

डॉ. रवजोत सिंह ने भरोसा देते हुए कहा कि समिति/कॉर्पोरेशन या विभाग स्तर पर हल किए जा सकने वाले सभी जायज मुद्दों को जल्दी हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो मांगें प्रदेश सरकार या अन्य विभागों से संबंधित हैं, उन्हें हल करने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

इस मौके पर स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह, निदेशक गुरप्रीत सिंह खैहरा के अलावा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा पंजाब वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड आउटसोर्स मजदूर यूनियन, पंजाब वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड एंप्लाइज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और लेबर यूनियन, म्यूनिसिपल मजदूर एक्शन कमेटी पंजाब और फायर ब्रिगेड आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन पंजाब के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

कायरतापूर्ण हिसंक घटनाओं से देश डरनेवाला नहीं है, आतंकियो को देश की सेना मुंहतोड़ जवाब देंगीः राजेश शुक्ला

पहलगाम घटना पर यमुनापार के जनप्रतिनिधियों एवं भाजपाइयों ने गहरा दुःख जताया

संजना भारती संवाददाता
मनोज कुमार बिन्द

प्रयागराज। भाजपा जिलाध्यक्ष यमुनापार राजेश शुक्ल ने पहलगाम घटना पर दुःख जताते हुए कहा यह घटना कायरतापूर्ण है। देश इस तरह की हिंसक घटनाओं से डरनेवाला नहीं। इसमें सम्मिलित आतंकियो को देश की सेना मुंहतोड़ जवाब देंगी। जिलाध्यक्ष ने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। पूर्व जिलाध्यक्ष विभवनाथ भारती ने कहा निःशब्द कर देने वाला घटना को ना देश बर्दाश्त करेगा ना देश की सेना इनके करनी का दण्ड अवश्य मिलेगा।

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी दिलीप कुमार चतुर्वेदी ने भारतीय नागरिको की कार्यरता पूर्ण हत्या पर दुःख जताते हुए कहा देश पाकिस्तान की नापाक इरादों से डरनेवाला नहीं है। कायरता पूर्ण हमले का मुंहतोड़ जबाव देश की सेना देगी। उरी और पुलवामा हमले के बाद की कार्रवाई को पाकिस्तान शायद भूल गया इस बार ना भूलने वालीं कार्यवाही को देश देखना चाहतीं है। पहलगाम घटना पर पूर्व सांसद प्रो.रीता बहुगुणा जोशी,भाजपा नेता नीरज त्रिपाठी, विधायक करछना पियूष रंजन निषाद, विधायक कोरांव राजमणि कोल, विधायक बारा डाँ. वाचस्पति, पूर्व विधायक इं. उदयभान करवरिया आदि ने घटना पर गहरा दुःख जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

राजधानी दिल्ली में काव्यपाठ करेंगे बेगूसराय के मिन्टू

एसबी संवाददाता

बेगूसराय। हिन्दुस्तान अंतरराष्ट्रीय साहित्य समूह द्वारा दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान भवन में 27 अप्रैल 2025 को आयोजित कवि सम्मेलन में युवा कवि मिन्टू को आमंत्रित किया गया है। इस उपलब्धि के लिए स्थानीय साहित्यकारों ने इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दिया।

तरुण सांस्कृतिक चेतना समिति के मीडिया प्रभारी मिन्टू के इस उपलब्धि पर तरुण सांस्कृतिक चेतना समिति के संस्थापक सीताराम शेरपुरी ने उनके उन्नति के सतदल पर आसीन होने की कामना की है। वहीं मिन्टू अपनी हास्य कविताओं से दर्शकों का लोटपोट करेंगे। मंच पर श्री झा दांत निपोरे नेता पहुंचे जनता से जब काम, दिल में रख मत पीर पराई, सर्वे भवन्तु सुखिनःका पाठ पढ़ाने आया हूं आदि की प्रस्तुति देंगे। डॉ. महेशचंद्र चौरसिया, प्रो.सत्यसंध भारद्वाज, श्रीराम राय, देवनीति राय, उमेश कुंवर, रंजना लता, अर्चना चौधरी, शौरव वाचस्पति, प्रवीण कुमार चुन्नू, मुकेश समस्तीपुरी, रेखा शर्मा आदि ने शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहलगाम आतंकी हमले को बताया निंदनीय

मुख्यमंत्री ने हरियाणा की पहली 'कम्प्लीट स्ट्रीट्स' का किया पैदल निरीक्षण

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि देश ऐसे कठिन समय में एकजुट है और आतंकवाद से डरने या झुकने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री ने हमले में मारे गए आम नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा की यह कायराना हरकत है, जिसने निर्दोष लोगों की जान ली। नागरिकों का बलिदान सदैव स्मरण रहेगा और हम उनके परिवारों के साथ खड़े रहेंगे।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले श्री विनय नरवाल के परिजनों से भी बात की। मुख्यमंत्री ने परिवार के साथ दुख साझा किया और कहा कि हरियाणा सरकार दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम के उद्योग विहार सेक्टर-18 में हरियाणा की पहली कम्प्लीट स्ट्रीट्स का पैदल निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कम्प्लीट स्ट्रीट्स राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसमें हर वर्ग, बच्चा, बुजुर्ग, महिला या दिव्यांग, को शहर में सम्मानपूर्वक और सुरक्षित रूप से चलने का अधिकार मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता केवल बुनियादी ढाँचे का निर्माण नहीं, बल्कि मानवीय विकास है। गुरुग्राम की इन सड़कों पर पैदल चलना, साइकिल चलाना, या बस पकड़ना अब केवल एक जरूरत नहीं, बल्कि एक सुखद अनुभव होगा। यह परियोजना दिखाती है कि जब सरकार, निजी क्षेत्र और सामाजिक संस्थाएं एक साथ आते हैं, तो हम कितने अद्भुत और स्थायी बदलाव ला सकते हैं। यह कम्प्लीट स्ट्रीट्स मॉडल केवल हरियाणा नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक उदाहरण बनेगा। यह कम्प्लीट स्ट्रीट्स परियोजना उद्योग विहार की सनथ रोड और गली नंबर-7 पर लागू की गई है, जो कुल 2.4 किलोमीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी है। यह सड़क पुरानी दिल्ली रोड को एयरटेल कार्यालय (ठल्र 48) से जोड़ती है। परियोजना की कुल लागत लगभग 23 करोड़ रुपये रही, जिसमें जीएमडीए, एमसीजी, डीएचबीवीएन और राहगीरी फाउंडेशन ने मिलकर योगदान दिया। इस परियोजना में राहगीरी फाउंडेशन के साथ-साथ नगरो, मारुति सुजुकी और सेफएक्सप्रेस जैसी कंपनियों ने भी भागीदारी की, जिससे सरकारी और निजी क्षेत्रों के सहयोग की एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की गई।

पैदल यात्रियों के लिए चौड़े और छायादार फुटपाथ, साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित ट्रैक, वर्षा जल संरक्षण के लिए बायोसवेल्स, और 700 पुराने पेड़ों का संरक्षण किया गया है। साथ ही 20,000 से अधिक फूलों के पौधे लगाए गए हैं। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चार प्रशिक्षित स्ट्रीट मार्शल भी 24 घंटे तैनात हैं। यह मॉडल आने वाले समय में पूरे हरियाणा और देश के अन्य शहरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा।

'आप सरकार' की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिमः रिश्वत लेता पटवारी विजिलेंस ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनाई गई जीरो सहिष्णुता नीति के तहत चल रही मुहिम में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने बुधवार को अमृतसर के राजस्व हल्का सुलतानविंड में तैनात राजस्व पटवारी हरप्रीत सिंह को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने इस संबंध में बताया कि अमृतसर के सुलतानविंड के एक व्यक्ति द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के बाद यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। उन्होंने आगे बताया कि शिकायतकर्ता ने

विजिलेंस ब्यूरो से संपर्क कर आरोप लगाया कि उक्त पटवारी ने उसके प्लॉट से संबंधित माल रिकॉर्ड में संशोधन करने के लिए 2,50,000 रुपये की रिश्वत मांगी है। शिकायत के अनुसार पटवारी ने शिकायतकर्ता से यह भी कहा कि रिश्वत की यह राशि तहसीलदार और गिरदावर के साथ भी साझा की जाएगी और वह इस राशि में से केवल 50,000 रुपये ही लेगा। प्रवक्ता ने आगे कहा कि इस शिकायत की प्राथमिक जांच के बाद अमृतसर रेंज की विजिलेंस ब्यूरो टीम ने जाल बिछाया और उक्त मुलज़िम को दो सरकारी गवाहों की हाजिरी में शिकायतकर्ता से 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। इस संबंध में मुलज़िम के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत अमृतसर रेंज के विजिलेंस ब्यूरो पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। मुलज़िम को कल सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा और आगे की जांच जारी है।

स्वास्थ्य मंत्री ने नशे के विरुद्ध लड़ाई में बच्चों को हीरो के रूप में नवाजा, उन्हें राजदूत बनने का आह्वान किया

डीसी और एसएसपी पटियाला के नेतृत्व में हजारों विद्यार्थी और निवासी मैराथन में

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़/पटियाला। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा शुरू की गई नशा विरोधी मुहिम 'युद्ध नशों विरुद्ध' को जोरदार बढ़ावा देते हुए पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज नशे के विरुद्ध राज्य की तेज लड़ाई में बच्चों को राजदूत बनने का आह्वान करते हुए ऐलान किया कि नशे के विरुद्ध प्रयासों को बढ़ावा देने वालों को राज्य सरकार द्वारा जिला और राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।

यह ऐलान स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आज सुबह पोलो ग्राउंड में डिप्टी कमिश्नर डॉ. प्रीति यादव और एस.एस.पी. डॉ. नानक सिंह के नेतृत्व में पोलो ग्राउंड से करवाई गई 'युद्ध नशों विरुद्ध' मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने बच्चों को हमारे असली हीरो बताते हुए प्रेरित किया कि वे खुद नशे से बचें और अपने आस-पास के लोगों को भी नशे के बुरे प्रभावों से अवगत कराएं।

विद्यार्थियों, अध्यापकों, समाज सेवकों और निवासियों के 10,000 से अधिक प्रतिभागियों की सभा को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के "रंगला पंजाब" के दृष्टिकोण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल वतन पंजाब की पहल के तहत हर गांव में खेल के मैदान और लाइब्रेरी बनाकर पंजाब को खेलों और शिक्षा के केंद्र में बदलने के लिए कार्य कर रही है। डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय आदर्श शहीद भगत सिंह, बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर और लाल बहादुर शास्त्री ने शिक्षा और राष्ट्रीय जागरूकता से राष्ट्रीय चेतना प्राप्त की। उन्होंने बच्चों से हमारे राष्ट्रीय नायकों से प्रेरणा लेने की अपील करते हुए कहा कि हमारे विद्यार्थी भी हमारे नायक हैं, जो जिंदगी में कभी नशा नहीं करेंगे और दूसरों के आदर्श बनकर दूसरों को भी नशे से बचाने के लिए पंजाब सरकार का साथ देंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने अल्बर्ट आइंस्टीन और एलन मस्क का जिक्र करते हुए कहा कि नशे तरक्की की राह में बेड़ियां हैं लेकिन शिक्षा उन्हें रास्ता दिखाती है। इसलिए पंजाब के बच्चों को शिक्षा के रास्ते पर चलना चाहिए और नशे के विरुद्ध लड़ाई में अग्रणी बनना चाहिए और सरकार द्वारा ऐसे विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर डॉ. प्रीति यादव ने मैराथन में भाग लेने वालों का स्वागत करते हुए कहा कि पटियाला के नौजवानों की उत्साही भागीदारी जिले को नशा मुक्त बनाने की ओर ले जाएगी। एस.एस.पी. डॉ. नानक सिंह ने इस महत्वपूर्ण मिशन में पंजाब पुलिस को लगातार समर्थन देने के लिए पटियाला के लोगों का धन्यवाद किया। इस कार्यक्रम के दौरान नशा विरोधी शपथ भी दिलाई गई और पद्म श्री प्राण सभरवाल के नेतृत्व में नेशनल थिएटर आर्ट्स सोसाइटी (एन.टी.ए.एस.) ने नशों के विरुद्ध एक शक्तिशाली नाटक पेश किया।

मैराथन में नगर निगम के मेयर कुंदन गोगिया, डिप्टी मेयर जगदीप सिंह जग्गा, जसबीर सिंह गांधी, बलविंदर सैनी, ए.डी.सी. नवनीत कौर सेखों, एस.पी. पलविंदर सिंह चीमा, संयुक्त कमिश्नर नगर निगम दीपजोत कौर और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

हरियाणा सरकार के आशीर्वाद से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने रचा इतिहास

नवीन मिश्रा के निर्देशन में सुपर 100' के 223 विद्यार्थियों में से 200 का जेई एडवांस्ड में हुआ चयन

सुपर सौ कैम्पस कुरुक्षेत्र। (छाया: एसबी)

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। हरियाणा सरकार के आशीर्वाद से सरकारी स्कूलों के होनहार विद्यार्थियों ने इतिहास रच दिया है। विकल्प फाउंडेशन के चेयरमैन नवीन मिश्रा के निर्देशन में "सुपर 100" के 223 विद्यार्थियों में से, 200 विद्यार्थियों का जेई एडवांस्ड में चयन होना हरियाणा के सरकारी स्कूलों के लिए गौरव की बात है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व प्रदेश में शिक्षा के आशीर्वाद से सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों ने सफलता की पताका फहराई है। हरियाणा सरकार की "सुपर सौ" योजना में विकल्प फाउंडेशन के अन्तर्गत नवीन मिश्रा के सानिध्य में कुरुक्षेत्र में नीट, मैडिकल, नोन मैडिकल की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों ने आशातीत सफलता हासिल कर प्रदेश के सरकारी स्कूल का कद ऊंचा कर दिया है। जेईई मेन्स परिक्षा परिणाम में सरकारी स्कूलों के 14 विद्यार्थियों ने 99 परसेंटाइल से ज्यादा अंक प्राप्त कर लोहा मनवाया है। 'सुपर 100' के 223 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इन में से 200 का जेई एडवांस्ड में चयन हुआ है। प्रदेश मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री ने भेजे संदेश में कहा कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर और बेहतर किया जाएगा।

हरियाणा में 'सुपर 100' योजना लागू करने का श्रेय तत्कालीन मुख्यमंत्री

हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी।

हरियाणा मनोहर लाल को (2017) जाता है।

वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 'सुपर 100' योजना को जारी रखा व मिशन बुनियाद योजना भी शुरू कर की (2022) में शुरूआत की थी। मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी व शिक्षा मंत्री महीपाल सिंह ढांडा ने अपनी योजनाओं से सरकारी स्कूल में जान डाल दी है।

हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग हरियाणा व नवीन मिश्रा, प्रदीप सेंसेरवाल व 'सुपर 100' की पूरी टीम को इस सफलता कि श्रेय जाता है। "सुपर 100" डायरेक्टर नवीन मिश्रा ने भेजे अपने सन्देश में बताया है कि हरियाणा सुपर 100 के विद्यार्थियों का आईआईटी, जेईई मेन्स 2025 का यह परिणाम शानदार रहा है। उन्होंने कहा कि उन बच्चों की संघर्ष की कहानी है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हुए हर चुनौती को पार करते गए और यह सिद्ध किया कि अगर एक अनुकूल माहौल मिले तो कोई भी शीर्ष मंचों तक पहुँच सकता है। यह परिणाम सरकारी स्कूल के हजारों अन्य विद्यार्थियों की सोच में एक नई उम्मीद पैदा करते हुए एक रचनात्मक परिवेश का निर्माण करेगा। अक्सर एक छोटी सी घटना ही एक बड़े परिदृश्य का निर्माण कर देती है।

नवीन मिश्रा ने मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी, शिक्षा मंत्री महीपाल सिंह ढांडा का सुपर सौ व मिशन बुनियाद श्रृजनातमक योजनाएं शुरू करने के धन्यवाद किया है। उन्होंने सभी सफल

शिक्षा मंत्री हरियाणा महीपाल सिंह ढांडा

विद्यार्थियों, अविभावकों, मेहनती व कर्मठ स्टाफ को शुभकामनाएं दी हैं।

गौरतलब है कि तात्कालीन मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार मनोहर लाल ने 2017 में हरियाणा के सरकारी स्कूल के दसवीं में पास विद्यार्थियों के लिए 'सुपर 100' योजना शुरू की थी। जिसके तहत कक्षा दसवीं पास करने के बाद विद्यार्थियों का प्रतियोगी परीक्षा के तहत चयन करके उन्हें रेवाड़ी में जेई व मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ 10 +1 व

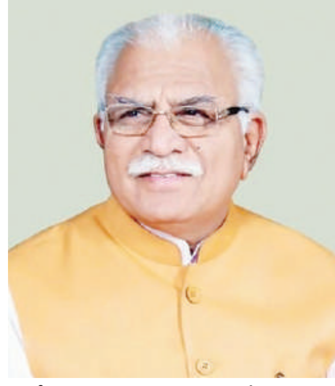
पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल

10 + 2 की पढ़ाई हरियाणा सरकार अपने खर्चे पर करवाने की योजना को धरातल पर उतारा गया था। विद्यार्थियों का रहने, खाने, वर्दी, पढ़ाई का पूरा खर्चा हरियाणा सरकार ने उठाया था। विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत, लग्न व "सुपर 100" के डायरेक्टर नवीन मिश्रा के निर्देशन में कड़ी मेहनत करते हुए आशा अनुरूप परिणाम देकर सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को आकाश की गहराई नापने के लिए उड़ान भरनी शुरू की। विद्यार्थियों ने आशा

विकल्प फाउंडेशन एवं सुपर सौ डायरेक्टर नवीन मिश्रा

अनुरूप परीक्षा परिणाम दे कर हरियाणा सरकार व नवीन मिश्रा के फैसले पर मोहर लगा दी। जहां प्राइवेट महंगे कोचिंग संस्थान कई-कई लाख रूपए की भारी भरकम फीस लेकर विद्यार्थियों को नीट व मेडिकल की तैयारी करवाते हैं। उन महंगे कोचिंग संस्थानों में लाखों विद्यार्थी ऑनलाइन व ऑफलाइन पढ़ने को मजबूर रहे हैं। इन लाखों विद्यार्थियों में से जहां संस्थाओं के लगभग 10 बच्चे 99% परसेंटाइल लेकर पास हो रहे हैं। वहीं "सुपर 100" संस्थान के तहत बिना कोई फीस दिए हरियाणा सरकार के आशीर्वाद व नवीन मिश्रा के सहयोग से 223 विद्यार्थियों में से 200 विद्यार्थियों ने जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। 14 विद्यार्थियों ने 99 परसेंटाइल से अधिक परिणाम दे कर महंगे प्राइवेट संस्थाओं के सामने सरकारी स्कूलों ने सफलता की एक नई रोशनी बिखेर कर अभिभावक को व

खंड राजौंद ब्लाक शिक्षा अधिकारी बलबीर सिंह कश्यप

विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में दाखिला ले कर पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है।

राजौंद खंड ब्लाक शिक्षा अधिकारी बलबीर सिंह कश्यप ने सभी सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूल के विद्यार्थी किसी भी मामले में निजी स्कूलों से पीछे नहीं है। उन्हें अगर सहयोग व अवसर मिले तो वह बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाला समय हरियाणा के सरकारी स्कूलों के लिए बेहतरीन होगा।

डीसी व एसपी ने किया गांव डोहर में ग्रामीणों से सीधा संवाद

नशे की बुराई को खत्म करने में गांव करेगा सहयोग, सभी बच्चों को भेजेंगे स्कूल

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। हरियाणा सरकार की 'रात्रि ठहराव' पहल के तहत बुधवार को डोहर गांव में जिला प्रशासन के रात्रि ठहराव कार्यक्रम में डीसी प्रीति व नवनियुक्त एसपी आस्था मोदी ने गांव के लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया। गांव के लोगों से सामाजिक बुराइयों के खात्मे को लेकर सीधी बातचीत की और गांव के लोगों ने भी नशे जैसी सामाजिक बुराईयों को खत्म करने में सहयोग का विश्वास दिलवाया।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लोगों से उनका लाभ उठाने का आह्वान किया। वहीं ग्राम पंचायत की ओर से सरपंच गीता, प्रतिनिधि मक्खन सिंह डोहर की अगुवाई में गांव में पहुंचने पर अधिकारियों का स्वागत किया। साथ ही जिला प्रशासन से गांव में टूटी पेयजल पाइप लाइन दुरुस्त करने, अवैध खुर्दे बंद करवाने, गांव में लाइब्रेरी खुलवाने की मांग रखी। गांव के लोगों ने भी डीसी के सामने पेंशन, आयुष्मान कार्ड, बिजली कनेक्शन, हैप्पी कार्ड, विकलांग पेंशन, आवास योजना, बिजली की लटकती तारों को ठीक करने जैसी अनेकों मांगें रखीं। डीसी ने मौके पर ही समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।

लोगों की समस्याएं सुनने के बाद अपने संबोधन में डीसी प्रीति ने अपने संबोधन में लोगों से गांव में नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने, धूम्रपान करने, बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करने जैसे विषयों पर सीधी बातचीत की। लोगों ने उन्हें कई बातों की जानकारी दी। डीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में नशे के खात्मे के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह एक बड़ी सामाजिक बुराई है। जिसे हमें स्वयं से पहल करके खत्म करना होगा। गांव में जो भी ठेके संबंधी शिकायत आई है, उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। यदि कहीं नशा किया जा रहा है तो प्रशासन को सूचना दें। गांव में यदि कोई बच्चा स्कूल से बाहर है, तो उसे स्कूल में दाखिल करवाएं।

नाबालिग बच्चों को दोपहिया वाहन चलाने को न दें। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें। कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। उन्होंने गांव की बेटी द्वारा आईआईटी में दाखिला लेने की सराहना करते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि गांव शिक्षा के प्रति जागरूक है। फिर भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएं। उन्होंने कहा कि गांव में जो भी समस्याएं इस कार्यक्रम में आई हैं, उनका समाधान करवाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने पहलगाम में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की हत्या होने पर परिवार को दी सांत्वना

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए नौसेना के लेफ्टिन विनय नरवाल के परिजनों से बातचीत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉल पर विनय नरवाल के दादा हवा सिंह से बात की और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के दादाजी से बातचीत करते हुए कहा कि दुःख की इस घड़ी में प्रदेश सरकार परिवार के साथ खड़ी है और जिन आतंकवादियों ने लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की हत्या की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पहलगाम में बातचीत कर रहे हैं और करनाल आकर भी परिवार से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिन परिवारों के साथ ये घटना हुआ है, उनके साथ पूर्ण रूप से केंद्र व प्रदेश की सरकार साथ खड़ी है।

इस मौके पर विधानसभा के अध्यक्ष एवं घरौंडा के विधायक हरविंद्र कल्याण ने लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की हत्या पर दुःख जताया और उनके घर जाकर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह बहुत ही दुखद घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। आज पूरा देश और पूरी दुनिया इस घटना की निंदा कर रही है। जिस प्रकार से बेकसूर नागरिकों को गोलियों से भूना गया, यह

मानवता के ऊपर एक हमला है। उन्होंने कहा कि ये घिनौनी घटना करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह हमला केवल हमारे नागरिकों के ऊपर नहीं, बल्कि पूरे देश के ऊपर हमला हुआ है। उन्होंने बताया कि देश के गृहमंत्री श्री अमित शाह कश्मीर में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विदेश दौरा बीच में छोड़कर इस दुःख की घड़ी में भारत पहुंच चुके हैं।

करनाल के विधायक जगमोहन आनंद ने मृतक विनय नरवाल के घर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार के साथ बातचीत की और फोन के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी सीधी बातचीत कराई। विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि दुःख की इस घड़ी में वे परिवार के साथ हैं और पहलगाम से वे पूरी अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि विनय नरवाल ने बिना हथियार के भी आतंकवादियों से लड़ाई लड़ी, ऐसे भारत माता के सपूत को शत-शत नमन है। असंध के विधायक योगेंद्र राणा ने कहा कि यह बहुत दुखदायी घटना है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि जिस प्रकार से पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी, दोबारा से उसी प्रकार की एक सर्जिकल स्ट्राइक और करनी चाहिए। केंद्र व प्रदेश सरकार ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इस दुःख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने पहुंची करनाल की मेयर रेनू बाला गुप्ता ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और प्रदेश का हर नागरिक इस दुःख की घड़ी में परिवार के साथ है।

इस मौके पर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के दादाजी ने बताया कि 16 अप्रैल को विनय की शादी हिमांशी के साथ हुई थी, दोनों शादी के बाद घूमने के लिए पहलगाम गए थे, जहां यह दर्दनाक घटना हुई है। उन्होंने बताया कि परिवार सेक्टर-7 में रहता है और पुश्तैनी घर घरौंडा विधानसभा के गांव भूसली में है। परिवार में उनके अलावा दादी, माता-पिता और छोटी बहन सृष्टि है।

ड्रग फ्री हरियाणा की अलख जगाते हुए कैथल जिला से रवाना हुई साइक्लोथॉन यात्रा

पुलिस लाइन से शिमला गांव तक जगह-जगह हुआ यात्रा का भव्य स्वागत

संजना भारती संवाददाता

कैथल/कलायत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नशा मुक्त हरियाणा की सोच को आगे बढ़ाते हुए साइक्लोथॉन यात्रा बुधवार को जींद जिला के लिए रवाना हो गई। यात्रा के दौरान युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं, खिलाड़ियों व दिव्यांगजनों ने अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज करवाई। जिस उत्साह और उमंग के साथ साइक्लोथॉन यात्रा का कैथल जिले में स्वागत हुआ, उसी जोश एवं विश्वास के साथ विदाई की गई।

पूंडरी के विधायक सतपाल जांबा, भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी, एडीसी दीपक बाबूलाल करवा, डीएसपी सुशील प्रकाश सहित अन्य ने बुधवार प्रातः पुलिस लाइन गणमान्य व्यक्तियों के साथ साइक्लोथॉन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक सतपाल जांबा ने कहा कि साइक्लोथॉन यात्रा प्रदेश की भावी पीढ़ी तथा युवाओं के लिए चरित्र निर्माण की दिशा में प्रेरणादायी साबित हो रही है। साइकिल का एक एक पैडल ड्रग फ्री हरियाणा की इस मुहिम को ताकत प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश तो इस कहावत से विख्यात है कि जित दूध-दही का खाणा, वो म्हारा हरियाणा। नशा व्यक्ति, परिवार व समाज का नाश कर देता है। साइकिल यात्रा के माध्यम से आमजन को नशे के विरुद्ध शुरू किए गए युद्ध में भागीदार बनते हुए नशा मुक्त हरियाणा का लक्ष्य प्राप्त करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने मे कैथल जिला ने अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की है।

ज्योति सैनी ने कहा कि यह यात्रा प्रदेश में सामाजिक कुरीति को जड़ से खत्म करने की दिशा में अहम साबित होगी। जन जागरूकता मुहिम के साथ मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी सबका साथ सबका विकास की विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य हरियाणा को नशा मुक्त बनाना है। हिसार से शुरू हुई यह साइक्लोथॉन पूरे राज्य में युवाओं को जोड़ते हुए एक सामाजिक परिवर्तन की अलख जगा रही है। उन्होंने आम नागरिकों से आह्वान किया कि वे इस अभियान से जुड़कर समाज को नशे की गिरफ्त से मुक्त कराने में अपना योगदान दें।

साइक्लोथॉन की अगुवाई कर रहे एसआई अशोक कुमार ने अपनी साइकिल पर लोटा सजाया हुआ है, जिसमें नागरिक नमक डालकर नशा न करने का संकल्प ले रहे हैं। उन्होंने युवा शक्ति को सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म करने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया।

यात्रा के गांवों में स्वागत समारोह के दौरान आमजन को जागरूकता कार्यक्रम में नशा न करने सहित नशे की बिक्री करने वाले लोगों की सूचना 9050891508, 1933 तथा मानस पोर्टल पर देने की शपथ भी दिलाई गई।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुआ आंतकी हमला घोर निंदनीय: अधिवक्ता सोनिया बोहत

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग

असन्ध। कांग्रेस नेत्री अधिवक्ता सोनिया बोहत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायरतापूर्ण और आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करती है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आंतकी हमले में लोगों के मारे जाने व घायल होने की घटना अतिदुखद, निंदनीय व चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी बर्बर घटनाएं न हों और निर्दोष भारतीय को इस तरह अपनी जान न गंवानी पड़े।

अधिवक्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुआ आंतकी हमला कायरतापूर्ण और घोर निंदनीय है। यह हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। सोनिया बोहत ने

घटना की निंदा करते हुए सरकार से इस पर कड़ा कदम उठाने की मांग की। कांग्रेस नेत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नफरत फैलाने की बजाय इस समय एकजुट होकर सरकार के साथ खड़े होकर आतंकियों के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए।

लक्ष्मी राइस मिल में लगी आग पर दमकल कर्मियों ने काबू पाया

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग

असन्ध। नगर के रतक रोड पर स्थित लक्ष्मी राइस मिल में अचानक आग लग गई। जिस कारण काम कर रहे मजदूरों व मिल मालिकों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी राकेश राणा व दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मिल के मालिक रामपाल गोयल ने बताया कि दोपहर बाद बॉयलर के छिलके के स्टोर पर मजदूर ने आग की लपटें उड़ती देखी। जिसकी जानकारी उसने मिल मालिक को दी।

रामपाल गोयल ने बताया कि धीरे-धीरे यह आग फैलने लगी परंतु दमकल कर्मियों ने समय रहते पहुंच कर आग पर काबू पा लिया। उन्होंने बताया कि अभी नुकसान का आंकलन नहीं किया गया है।

उन्होंने बताया कि इस घटना में कोई हाताहत नहीं हुआ है।

राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय असंध श्रेष्ठ विज्ञान विद्यालय घोषित: अजमेर सिंह

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग

असंध। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, असंध के प्रधानाचार्य अजमेर सिंह ने बताया शिक्षा विभाग, करनाल द्वारा असंध ब्लॉक के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय असंध को श्रेष्ठ विज्ञान विद्यालय घोषित करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त करनाल यश जालुका और जिला शिक्षा अधिकारी सुदेश ठुकराल ने विद्यालय के प्रधानाचार्य अजमेर सिंह सिंधु को सम्मानित किया।

इस संबंध में प्रधानाचार्य अजमेर सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग करनाल द्वारा पांच वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का चयन श्रेष्ठ विज्ञान विद्यालय के लिए किया गया है जिनके असंध का यह विद्यालय भी सम्मिलित है। उन्होंने बताया कि संपर्क फाउंडेशन द्वारा जारी सर्वेक्षण में भी

विज्ञान अध्यापिका की अपने विषय में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रशंसा की गई है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष भी विद्यालय की छात्रा पायल गर्ग ने जिला करनाल में प्रथम स्थान प्राप्त किया था तथा सात अन्य छात्राओं ने सत प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। उन्होंने इसके लिए सभी स्टाफ को भी बधाई दी और सभी अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि अपनी बेटियों के सुरक्षित एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय असंध में दाखिला करवाए।

जीवन चानन महाविद्यालय में वाणिज्य विभाग द्वारा विस्तार व्याख्यान का किया आयोजन

संजना भारती संवाददाता

असन्ध। जीवन चानन महिला महाविद्यालय में वाणिज्य विभाग के द्वारा एक विस्तार व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस विस्तार व्याख्यान के मुख्य वक्ता राजकीय महिला महाविद्यालय करनाल से प्रोफेसर रमेश कुमार रहे। वाणिज्य विभागाध्यक्ष सुषमा शर्मा ने पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। उन्होंने छात्राओं को स्टॉक मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग कैसे की जाती है उसके बारे में बड़े ही विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से डिमैट अकाउंट खोला जाता है और उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है। इसके साथ-साथ बहुत सारे अन्य प्लेटफॉर्म्स भी उन्होंने अपने व्याख्यान में विस्तार पूर्वक बताएं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके बच्चे स्वयं को आज के डिजिटल युग में अपने आप को कामयाब बना सकते है। स्टॉक मार्केटिंग की तरफ

सभी का रुझान होता जा रहा है। उसमें हम किस प्रकार से अपने आप को कामयाब कर सकते हैं इसके बारे में उन्होंने छात्राओं को बताया।

वाणिज्य विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुषमा शर्मा ने बताया कि वह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। उसमें शेयर्स को कैसे खरीदना और बेचना है इसके बारे में बच्चों को विस्तार पूर्वक बताया गया।

इस अवसर पर सपना, मनीषा फोगाट, डॉ. हेमलता शर्मा, अदिति, डॉ. रेखा बंसल, राजविंदर सहित अन्य मौजूद रहे।

पंचकूला में आज होगा राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान सम्मेलन

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजेश कुमार

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को अधिक सक्षम और जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से 24 अप्रैल, 2025 को पंचकूला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस महत्त्वपूर्ण सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार करेंगे।

यह सम्मेलन कई मायनों में खास होगा। एक ओर जहां इस सम्मेलन में पंचायतों की कार्यप्रणाली, फंड के उपयोग और विकास कार्यों की रियल-टाइम जानकारी के संबंध में जानकारी मिलेगी, वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को भी बड़ा तोहफा मिलेगा। इस सम्मेलन के दौरान ही, मुख्यमंत्री द्वारा मार्च महीने में पहचान किए गए 41,591 नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण भी किया जाएगा। यह कदम प्रदेश के पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की दिशा में एक और मजबूत प्रयास है।

गौरतलब है कि, वर्तमान में हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 34,95,507 पात्र लाभार्थियों को पेंशन/वित्तीय सहायता का लाभ पीएफएमएस के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में प्रदान किया जा रहा है।

यह आयोजन ग्रामीण विकास, प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक निर्णायक कदम सिद्ध होगा। सम्मेलन में प्रदेशभर से हजारों की संख्या में पंचायती राज प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेंगे, जिनमें महिला प्रतिनिधियों की विशेष और उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिलेगी। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता का एक जीवंत उदाहरण होगा।

इस सम्मेलन का उद्देश्य केवल पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाना ही नहीं है, बल्कि राज्य भर के जनप्रतिनिधियों, विशेषकर महिला प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और योजनाओं की विस्तृत जानकारी देकर उन्हें और अधिक प्रभावशाली तथा आत्मनिर्भर बनाना भी है।